

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 199
उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

उच्चतर शिक्षा में आत्मनिर्भरता

199. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में बौद्धिक क्षमता, नवाचार और शिक्षा से संबंधित मजबूत नीतियों के माध्यम से भविष्य के निर्माण में युवाओं की मदद करने हेतु क्या प्रयास किए गए/किए जा रहे हैं;

(ख) आने वाले वर्षों में देश, विशेषकर गुजरात, को उच्चतर शिक्षा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या प्रयास किए गए/किए जा रहे हैं; और

(ग) सम्पूर्ण देश में प्रतिभा पलायन के परिदृश्य को प्रतिभा अर्जन में बदलने और देश को ज्ञान केंद्र बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए/किए जा रहे हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ग): बौद्धिक क्षमता, नवाचार और शिक्षा से संबंधित प्रभावी नीतियों के साथ नए भविष्य के निर्माण में युवाओं की मदद करने के लिए, भारत सरकार ने 29.07.2022 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की है। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है जिसका मूल स्रोत भारतीय लोकाचार में निहित है, यह सभी लोगों को नवाचार व अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर इंडिया अर्थात भारत को सतत रूप से एक समान एवं उदीयमान ज्ञान के समाज में रूपांतरित करने में सीधा योगदान देती है ताकि भारत के छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करके भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाया जा सके।

देश को उच्च शिक्षा में आत्मनिर्भर और एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए, उच्च शिक्षा संस्थान उच्च शिक्षा व्यवस्था जिसमें बड़े, बहु-विषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हैं, की ओर अग्रसर हैं जो स्थानीय/भारतीय भाषाओं में शिक्षण का माध्यम या कार्यक्रम प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान बढ़े हुए उद्योग-शैक्षणिक संबंधों के साथ स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन केंद्र, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र आदि स्थापित करके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों ने कौशल, रोजगार और उद्यमिता विकसित करने के लिए इंटरनशिप / अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम शुरू किए हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कई शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए हैं जैसे 7 नए आईआईएम (सिरमौर, नागपुर, संबलपुर, अमृतसर, बोधगया, विशाखापत्तनम और जम्मू), 6 नए आईआईटी (तिरुपति, पलक्कड, जम्मू, भिलाई, गोवा, धारवाड़) और आईएसएम धनबाद को आईआईटी में परिवर्तित किया गया, 2 नए आईआईएसईआर (तिरुपति और बेहरामपुर), 01 नया एनआईटी (आंध्र प्रदेश), 20 आईआईआईटी - पीपीपी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान (आईएनआई) घोषित किया गया, 16 आईआईआईटी (15 आईआईआईटी - पीपीपी और 1 आईआईआईटी कुरनूल), मोतिहारी, बिहार में 01 नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

सरकार न केवल देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों से पास होने वाले छात्रों को बनाए रखने बल्कि प्रवासी भारतीयों को भी देश में वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधान मंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना के तहत, चयनित छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों से पीएचडी करने के लिए आकर्षक फेलोशिप प्रदान की जाती है। सरकार ने देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए आईआईटी-मद्रास, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, गांधीनगर और आईआईएससी बेंगलोर में अनुसंधान पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है ताकि छात्रों को भारत में अभिनव अनुसंधान के माध्यम से अपने अनुसंधान एवं विकास हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। शैक्षिक संस्थानों में इनक्यूबेशन सेंटर (आईसी) उद्यमियों को प्रतिस्पर्धी माहौल में बने रहने और उस मुकाम, जहां वे अपने उद्यमों को और आगे बढ़ा सकते हैं, पर पहुंचने में सहायता देने के लिए उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करके उनके स्टार्ट-अप फेज के माध्यम से प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित उद्यमों का विकास करते हैं।
